

Rajasthan Takes Stock of Saksham Anganwadi, Poshan 2.0 and Mission Shakti



The Chief Secretary, V. Srinivas, recently chaired a review meeting of Saksham Anganwadi, Poshan 2.0 and Mission Shakti in Jaipur. The review meeting was in connection with the Directorate of ICDS and the Directorate of Women Empowerment of the Women and Child Development Department. The State Empowered Programme Committee also discussed the implementation of key welfare schemes. The Chief Secretary instructed the officials to follow the directions of the Government of India as given in the Fifth National Chief Secretaries' Conference. This meeting is relevant for the RAS exam study as it deals with nutrition, empowerment of women, child welfare, inter-departmental coordination and delivery of services at the grassroots level.

Meeting Highlights

- Chief Secretary V. Srinivas presided over the meeting.
- Saksham Anganwadi, Poshan 2.0 and Mission Shakti were reviewed.
- The meeting was held in coordination with the Directorate of ICDS and Directorate of Women Empowerment.
- The State Empowered Programme Committee discussed the scheme.
- Action plan was directed to be prepared for following up the instructions of the Government of India.

- The Chief Secretary also asked to respond to the letters received from the Government of India in a timely manner.

Emphasis on Improved Scheme Implementation

Coordination among Departments

- The Chief Secretary emphasised coordination among other departments related to women and child development schemes.
- The aim is to ensure timely benefits to the beneficiaries.
- This is crucial for successful implementation of nutrition, empowerment of women and child development schemes.

One Stop Centres

- An instruction was given to visit One Stop Centres.
- Services at these centres need to be improved.
- This is important for the safety of women, support services and institutional responsiveness.

Lado Yojana Portal and Online Review

- The Chief Secretary asked for a separate meeting with the Education Department and other concerned departments to enhance the Lado Yojana portal.
- The Vidya Samiksha Kendra portal was also to be reviewed for this purpose.
- This reflects the increasing emphasis on online monitoring and effective portal governance in Rajasthan.

Strengthening Anganwadi Centres

Colocation with Government Schools

- The Chief Secretary asked the officials to fast-track the colocation of Anganwadi centres with government schools in the vicinity.
- This will ensure better access, tracking and integration of early childhood care and education with schooling.

Training of Anganwadi Workers

- Champion Anganwadi workers should be trained about departmental schemes.
- They should also be given regular webinars.
- This may enhance their knowledge, capacity and delivery of services at the grassroots level.

Participation of Fathers

- The Chief Secretary directed that the involvement of fathers should be increased in the parent-worker meetings at Anganwadi centres.
- This will promote shared responsibility in nutrition, care in early childhood and awareness at family level.

Basic Facilities at Anganwadi Centres

- Instructions were issued for upgradation of basic facilities at Anganwadi centres.
- This should be through convergence with the other departments.
- This shows the need for infrastructure improvement in service provision.

Approval of ICDS APIP 2026-27

- During the review meeting, the ICDS APIP 2026-27 was approved.
- This helps in the planning and roll-out of Integrated Child Development Services for the next financial year.
- This will help in implementing child development and nutrition related schemes.

Conclusion

The review of Saksham Anganwadi, Poshan 2.0 and Mission Shakti shows the focus of Rajasthan on enhancing nutrition, women empowerment and child development programmes. The directives to ensure inter-departmental coordination, portal development, Anganwadi strengthening, inspection of One Stop Centre and engagement of fathers can enhance governance and service delivery.

MCQs

MCQ 1: Who presided over the review of Saksham Anganwadi, Poshan 2.0 and Mission Shakti in Jaipur?

- A. Chief Minister Bhajanlal Sharma
- B. Chief Secretary V. Srinivas
- C. Minister for Women and child development
- D. Education Secretary

Answer: B

Answer: The meeting was convened by Chief Secretary V. Srinivas. It discussed various schemes of the Women and Child Development Department such as Saksham Anganwadi, Poshan 2.0 and Mission Shakti.

MCQ 2: Which portal was it recommended to evaluate for the improvement of the Lado Yojana portal?

- A. Jan Aadhaar Portal
- B. e-Mitra Portal
- C. Vidya Samiksha Kendra Portal
- D. Raj-Kisan Portal

Answer: C

Explanation : The Chief Secretary said the Vidya Samiksha Kendra portal will be reviewed to make the Lado Yojana portal better. He also directed to have a separate meeting with the Education Department and other departments.

MCQ 3: Which of the following was passed in the review meeting?

- A. Mission Shakti Annual Report 2025-26
- B. ICDS APIP 2026-27
- C. Lado Yojana Budget 2026-27
- D. State Nutrition Survey 2026

Answer: B

Explanation : The review meeting has given approval to ICDS APIP 2026-27. This will help in the planning and implementation of Integrated Child Development Services (ICDS) for nutrition, child development and welfare services in Rajasthan.

राजस्थान में सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन शक्ति की समीक्षा

जयपुर में मुख्य सचिव **वी. श्रीनिवास** की अध्यक्षता में **सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन शक्ति** की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय और महिला अधिकारिता निदेशालय से संबंधित थी। इस बैठक में राज्य सशक्त कार्यक्रम समिति ने भी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को **पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन** में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह विषय आरएएस परीक्षा की

दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पोषण, महिला सशक्तीकरण, बाल विकास, विभागीय समन्वय और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण से संबंधित है।

बैठक के प्रमुख बिंदु

- बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।
- सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन शक्ति की समीक्षा की गई।
- बैठक समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय और महिला अधिकारिता निदेशालय से संबंधित थी।
- राज्य सशक्त कार्यक्रम समिति ने योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
- भारत सरकार के निर्देशों की पालना के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए।
- भारत सरकार से प्राप्त पत्रों का उत्तर समय पर भेजने के भी निर्देश दिए गए।

कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर

विभागों के बीच समन्वय

- मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से जुड़े अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
- इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है।
- पोषण, महिला सशक्तीकरण और बाल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह समन्वय आवश्यक है।

एकल सहायता केंद्र

- एकल सहायता केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए।
- इन केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया।
- यह महिला सुरक्षा, सहायता सेवाओं और संस्थागत जवाबदेही की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

लाडो योजना पोर्टल और डिजिटल समीक्षा

- मुख्य सचिव ने लाडो योजना पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
- इस उद्देश्य से विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल का अवलोकन करने को भी कहा गया।
- यह राजस्थान में डिजिटल निगरानी और पोर्टल आधारित शासन के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने पर जोर

राजकीय विद्यालयों के साथ सह-स्थान

- मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी राजकीय विद्यालयों के साथ सह-स्थित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

• इससे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विद्यालयी शिक्षा के बीच बेहतर जुड़ाव, निगरानी और पहुंच सुनिश्चित हो सकती है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

- चैंपियन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय योजनाओं के संबंध में नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए।
- उनके लिए नियमित रूप से वेबिनार आयोजित करने को भी कहा गया।
- इससे जमीनी स्तर पर जागरूकता, कार्य क्षमता और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है।

पिता की भागीदारी

- आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित अभिभावक-कार्यकर्ता बैठकों में बच्चों के पिता की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- यह बाल पोषण, प्रारंभिक देखभाल और परिवार स्तर पर जागरूकता में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं

- आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- इसके लिए संबंधित विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रगति लाने को कहा गया।
- यह सेवा वितरण में बुनियादी ढांचे के सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

समेकित बाल विकास सेवा की वार्षिक योजना 2026-27 को अनुमोदन

- समीक्षा बैठक में समेकित बाल विकास सेवा की वार्षिक योजना 2026-27 को अनुमोदित किया गया।
- यह आगामी वित्तीय वर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की योजना और क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।
- इससे बाल विकास और पोषण संबंधी कार्यक्रमों के बेहतर संचालन में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन शक्ति की समीक्षा राजस्थान में पोषण, महिला सशक्तीकरण और बाल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने की दिशा को दर्शाती है। विभागीय समन्वय, पोर्टल सुधार, आंगनबाड़ी सुदृढीकरण, एकल सहायता केंद्रों के निरीक्षण और पिता की भागीदारी बढ़ाने जैसे निर्देश जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1: जयपुर में सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन शक्ति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की?

- A. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
- B. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास
- C. महिला एवं बाल विकास मंत्री
- D. शिक्षा सचिव

उत्तर: B

व्याख्या: बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई।

प्रश्न 2: लाडो योजना पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए किस पोर्टल का अवलोकन करने के निर्देश दिए गए?

- A. जन आधार पोर्टल
- B. ई-मित्र पोर्टल
- C. विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल
- D. राज-किसान पोर्टल

उत्तर: C

व्याख्या: मुख्य सचिव ने लाडो योजना पोर्टल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल का अवलोकन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने को भी कहा गया।

प्रश्न 3: समीक्षा बैठक में निम्नलिखित में से किसे अनुमोदित किया गया?

- A. मिशन शक्ति वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26
- B. समेकित बाल विकास सेवा की वार्षिक योजना 2026-27
- C. लाडो योजना बजट 2026-27
- D. राज्य पोषण सर्वेक्षण 2026

उत्तर: B

व्याख्या: समीक्षा बैठक में समेकित बाल विकास सेवा की वार्षिक योजना 2026-27 को अनुमोदित किया गया। यह राजस्थान में पोषण, बाल विकास और कल्याणकारी सेवाओं की योजना तथा क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

**Global Rajasthan Agritech Meet
2026 Investor Meet at Ahmedabad**



Chief Minister Bhajanlal Sharma called for investments for Rajasthan's agriculture revolution at the Global Rajasthan Agritech Meet 2026 Investor Meet held in Ahmedabad. The Chief Minister said that Rajasthan is well poised to emerge as an agri-business hub because of its multiple crop production of bajra, mustard, isabgol and cumin. The meet highlighted opportunities in agriculture, agritech, animal husbandry, dairy, food and spice processing, cold chain, drones and artificial intelligence in agriculture. The main GRAM 2026 will be held in Jaipur from 23 to 25 May.

Investor Meet Highlights

- GRAM 2026 Investor Meet was held in Ahmedabad.
- Investors were greeted by Chief Minister Bhajanlal Sharma.
- Investors were encouraged to attend the main GRAM 2026 event in Jaipur from 23-25 May.
- Agriculture, agritech, animal husbandry and dairy were key topics of discussion.
- Business opportunities were explored in food processing, food parks, spice processing, cold chain and technology in agriculture.
- MoU for dairy, food parks, food processing and spice processing was signed.
- Chief Minister launched the Ahmedabad Chapter of Rajasthan Foundation.

Rajasthan has Potential to be an Agri-Business Hub

Rajasthan has a diverse agricultural economy. It is the top producer of bajra, mustard, isabgol and cumin. This provides an opportunity for Rajasthan to emerge as India's agri-business hub.

According to the Chief Minister, GRAM 2026 will provide new opportunities for investment in food processing sector, agriculture parks and agri-based farms. The summit can help Rajasthan to transform its agriculture to the market-oriented and technology-based one with the help of investors, scientists, startups and policy makers.

GRAM 2026 Investment Opportunities

Major Focus Areas

- Agriculture and agritech
- Food processing
- Drone technology
- Artificial intelligence-based farming
- Cold chain infrastructure
- Dairy and animal husbandry
- Food parks and spice processing
- Organic farming

Importance for Rajasthan

- Farmers can get better market opportunities.
- It can help in value addition of farm products.
- It can generate rural and semi-urban jobs.
- It can increase supply chain links with other states.
- It can encourage local and foreign investment in Rajasthan's agriculture.

Food Processing and Food Parks in Rajasthan

- The Chief Minister said Rajasthan and Gujarat have similar agricultural economies. So, it will be beneficial for both states to set up food processing units and supply chains. This will enable farmers to get better markets and remunerations.
- Rajasthan already has more than 1,500 food processing units with investment of more than ₹3,500 crore. The state government has also targeted to set up 39 food parks; land has already been identified at 34 sites for the same.

Commitments at Rising Rajasthan Summit

- The Chief Minister said that Rajasthan is already making efforts to attract investments. MoUs worth of around ₹44,000 crore were signed in agriculture during the Rising Rajasthan Global Investment Summit. In this, investment of around ₹10,000 crore has been laid.
- The government has also constructed 46,000 kilometres of road in the last two years for industrial and investment infrastructure. Transparent policies,

processes and a fast-track decision-making process are being encouraged to support investors.

Farmers' and Agriculture Support

Farmer Welfare Initiatives

- More than 76 lakh farmers have been given more than ₹12,000 crore directly into their bank accounts under the Samman Nidhi scheme.
- More than ₹6,500 crore has been disbursed as insurance claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.
- 2.20 crore insurance policies have been issued.
- Over 65,000 solar pump sets have been installed under PM-KUSUM.
- More than 78 lakh farmers have been provided with more than ₹52,000 crore of interest-free short-term loan for crop.
- Interest-free loans up to ₹1 lakh are being given under the Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Loan Scheme.

Infrastructure, Energy and Water Support

- The Chief Minister said Rajasthan is working towards energy security. The state government has added 8,670 MW of power generation in two years. Power is being provided to farmers of 24 districts during the day.
- The Ram Jal Setu Link Project for 17 districts and Yamuna water agreement MoU for Shekhawati have also commenced work. Upgrading of Devas, IGNP and Gangnagar projects will help in irrigating thousands of hectares in the coming years. The Karmabhoomi Se Matrubhoomi campaign is also contributing in water conservation and groundwater recharge.

Conclusion

Ahmedabad's GRAM 2026 Investor Meet is part of Rajasthan's goal to modernise agriculture to make it technology-focused and attractive to investments. The state plans to boost rural development and position itself as a leading centre for agri-business in India by emphasising agritech, food processing, dairy, cold chain, irrigation, energy and farmer welfare.

MCQs

MCQ 1: Where was the GRAM 2026 Investor Meet organised and addressed by Chief Minister Bhajanlal Sharma held?

- A. Jaipur
- B. Ahmedabad

C. New Delhi

D. Bengaluru

Answer: B

Explanation: GRAM 2026 Investor Meet was held in Ahmedabad where Chief Minister Bhajanlal Sharma will appeal to investors to join Rajasthan in its agricultural revolution and the main event of GRAM 2026 which will take place in Jaipur from 23 to 25 May.

MCQ 2: Rajasthan will develop how many food parks for food processing?

A. 24

B. 34

C. 39

D. 46

Answer: C

Explanation: Rajasthan has proposed to set up 39 food parks for food processing. 34 sites have been identified. This move is significant in terms of value addition, improved marketing and income generation for farmers.

MCQ 3: What were the sectors that were linked in the MoUs signed at the Ahmedabad Investor Meet?

A. Dairy, food parks, food processing and spice processing

B. Textiles, tourism, mining and solar

C. Education, health, urban development and transport

D. Defence, electronics, automobiles and cement

Answer: A

Explanation : At the Ahmedabad Investor Meet, MoUs in dairy, food parks, food processing and spice processing were signed. These are directly related to the state's focus on agri-business, value addition and investment in agriculture-based industries.

अहमदाबाद में वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 निवेशक बैठक

अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 निवेशक बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की कृषि क्रांति के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजरा, सरसों, ईसबगोल और जीरा जैसे विविध कृषि उत्पादन के कारण राजस्थान के पास कृषि-व्यवसाय केंद्र के रूप में उभरने की मजबूत क्षमता है। बैठक में कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, पशुपालन, डेयरी, खाद्य और मसाला प्रसंस्करण, शीत शृंखला, ड्रोन और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े अवसरों पर चर्चा हुई। मुख्य सम्मेलन जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होगा।

निवेशक बैठक के प्रमुख बिंदु

- वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 निवेशक बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को संबोधित किया।
- निवेशकों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले मुख्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
- कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, पशुपालन और डेयरी प्रमुख चर्चा के विषय रहे।
- खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य उद्यान, मसाला प्रसंस्करण, शीत शृंखला और कृषि में तकनीक से जुड़े व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा हुई।
- डेयरी, खाद्य उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण और मसाला प्रसंस्करण से जुड़े समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ।
- मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन के अहमदाबाद अध्याय का शुभारंभ किया।

कृषि-व्यवसाय केंद्र बनने की राजस्थान की क्षमता

राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था विविध है। राज्य बाजरा, सरसों, ईसबगोल और जीरा के उत्पादन में अग्रणी है। यह विविधता राजस्थान को भारत के प्रमुख कृषि-व्यवसाय केंद्र के रूप में विकसित होने का अवसर देती है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि उद्यानों और कृषि-आधारित उद्यमों में निवेश के नए अवसर प्रदान करेगा। निवेशकों, कृषि वैज्ञानिकों, नव उद्यमों और नीति निर्माताओं की भागीदारी से राजस्थान की कृषि को बाजार आधारित और तकनीक आधारित दिशा मिल सकती है।

वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 में निवेश के अवसर

प्रमुख केंद्र क्षेत्र

- कृषि और कृषि-प्रौद्योगिकी
- खाद्य प्रसंस्करण

- ड्रोन तकनीक
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खेती
- शीत शृंखला अवसंरचना
- डेयरी और पशुपालन
- खाद्य उद्यान और मसाला प्रसंस्करण
- जैविक खेती

राजस्थान के लिए महत्व

- किसानों को बेहतर बाजार अवसर मिल सकते हैं।
- कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल सकता है।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो सकता है।
- अन्य राज्यों के साथ आपूर्ति शृंखला संबंध मजबूत हो सकते हैं।
- राजस्थान की कृषि में देशी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है।

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य उद्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और गुजरात की कृषि अर्थव्यवस्था में समानताएं हैं। इसलिए दोनों राज्यों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और आपूर्ति शृंखलाओं का विकास लाभकारी हो सकता है। इससे किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आय मिल सकती है।

राजस्थान में पहले से 1,500 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जिनमें ₹3,500 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। राज्य सरकार ने 39 खाद्य उद्यानों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 34 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा चुकी है।

राइजिंग राजस्थान सम्मेलन में निवेश प्रतिबद्धताएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान निवेश आकर्षित करने के लिए पहले से प्रयास कर रहा है। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में लगभग ₹44,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन हुए। इनमें से लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है।

सरकार ने औद्योगिक और निवेश अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पिछले दो वर्षों में 46,000 किलोमीटर सड़क का विकास किया है। निवेशकों को सहयोग देने के लिए स्पष्ट नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और त्वरित निर्णय प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।

किसानों और कृषि के लिए समर्थन

किसान कल्याण पहल

- सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76 लाख से अधिक किसानों को ₹12,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ₹6,500 करोड़ से अधिक के बीमा दावे वितरित किए गए हैं।
- 2.20 करोड़ बीमा पॉलिसियां बनाई गई हैं।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 65,000 से अधिक सौर पंप सेट स्थापित किए गए हैं।
- 78 लाख से अधिक किसानों को ₹52,000 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है।
- राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

अवसंरचना, ऊर्जा और जल समर्थन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने दो वर्षों में 8,670 मेगावाट बिजली क्षमता की वृद्धि की है। 24 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना और शेखावटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता जापन पर कार्य शुरू हो चुका है। देवास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंगानहर परियोजनाओं के सुदृढीकरण से आने वाले वर्षों में हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकती है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान भी जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में योगदान दे रहा है।

निष्कर्ष

अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 निवेशक बैठक राजस्थान की कृषि को आधुनिक, तकनीक आधारित और निवेश अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कृषि-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, शीत शृंखला, सिंचाई, ऊर्जा और किसान कल्याण पर बल देकर राज्य ग्रामीण विकास को मजबूत करने और भारत के प्रमुख कृषि-व्यवसाय केंद्र के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संबोधित वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 निवेशक बैठक कहां आयोजित हुई?

- A. जयपुर
- B. अहमदाबाद
- C. नई दिल्ली
- D. बेंगलुरु

उत्तर: B

व्याख्या: वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 निवेशक बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों से राजस्थान की कृषि क्रांति में सहभागी

बनने और 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित होने वाले मुख्य सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान किया।

प्रश्न 2: खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कितने खाद्य उद्यान विकसित करने की योजना बना रहा है?

- A. 24
- B. 34
- C. 39
- D. 46

उत्तर: C

व्याख्या: राजस्थान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 39 खाद्य उद्यान विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 34 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। यह पहल कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, बेहतर बाजार उपलब्धता और किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 3: अहमदाबाद निवेशक बैठक में हुए समझौता ज्ञापन किन क्षेत्रों से संबंधित थे?

- A. डेयरी, खाद्य उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण और मसाला प्रसंस्करण
- B. वस्त्र, पर्यटन, खनन और सौर ऊर्जा
- C. शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय विकास और परिवहन
- D. रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और सीमेंट

उत्तर: A

व्याख्या: अहमदाबाद निवेशक बैठक में डेयरी, खाद्य उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण और मसाला प्रसंस्करण से जुड़े समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। ये क्षेत्र राजस्थान की कृषि-व्यवसाय, मूल्य संवर्धन और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति से सीधे जुड़े हुए हैं।

Rajasthan Wildlife Census 2025 and Wildlife Outside Sanctuaries and Parks



The Wildlife Census 2025 conducted in Rajasthan reveals a significant trend in the state's forest and wildlife conservation. On Buddha Purnima at 5 PM, the Forest Department is counting wildlife using the waterhole method, which counts wildlife around water sources. Data from 2014 to 2025 shows that Rajasthan's estimated wildlife population increased from 21,759 in 2014 to 2,71,813 in 2025. Most importantly, wildlife outside protected areas is considerably greater than inside sanctuaries and parks. In 2025, 58,885 animals were found in sanctuaries and parks whereas 2,12,928 animals were counted outside sanctuaries and parks.

Wildlife Census 2025 Key Points

- Rajasthan recorded a total wildlife count of 2,71,813 in 2025.
- 58,885 animals were found inside sanctuaries and parks.
- 2,12,928 animals were found outside the sanctuaries and parks.
- The number of animals outside protected areas is more than three times that of sanctuaries and parks.
- Buddha Purnima brings the waterhole method of census.
- Ranthambore, Sariska and Mukundra Hills Tiger Reserves are not part of this data set as the method of counting is different.

Wildlife Growth from 2014 to 2025

In Rajasthan, the number of wildlife has grown significantly over the past 11 years. In 2014, the estimated count was 21,759, which increased to 2,71,813 in 2025. This indicates a significant increase in wildlife count in the state.

| Year | Total Wildlife | Inside Parks/Sanctuaries | Outside Protected Areas |
|------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 2014 | 21,759 | Data not available | Data not available |
| 2017 | 2,23,933 | Data not available | Data not available |
| 2018 | 2,55,304 | 50,545 | 2,04,759 |
| 2019 | 2,52,342 | 66,837 | 1,85,505 |
| 2020 | 2,32,468 | 41,805 | 1,90,663 |
| 2022 | 2,43,284 | 56,378 | 1,86,906 |
| 2024 | 2,53,713 | 57,316 | 1,96,397 |
| 2025 | 2,71,813 | 58,885 | 2,12,928 |

Major Wildlife Found Outside Protected Areas

There were many wildlife species that were present in greater numbers outside sanctuaries and parks. This suggests that the wildlife conservation in Rajasthan cannot be confined to protected areas.

| Species | Outside Sanctuaries/Parks | Inside Sanctuaries/Parks | Total |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| Nilgai/Rojda | 74,549 | 80 | 74,629 |
| Chinkara | 12,385 | 15 | 12,400 |
| Chital | 279 | 36 | 315 |

Why the Data Is Important

Conservation Beyond Protected Areas

- Rajasthan's wildlife is largely found outside protected areas based on the data.
- This increases the need to engage the community in village-based conservation and conservation outside sanctuaries.
- Movement of wildlife outside protected areas also means improved waterhole, pasture and forest management.

Value of the Waterhole Method

- The waterhole method will count wildlife around water bodies.
- In arid Rajasthan the animals generally visit water points at least once a day.
- It can be used to count wildlife on Buddha Purnima.

Data collection and census enhancement

Previous wildlife census was sparse. Between 2001 and 2004, just the name of animals and small figures were entered. Until 2013, full data for the whole state was also not available. From 2014 onwards, the total numbers were recorded. Therefore, the data since 2014 is more reliable for wildlife trends in Rajasthan.

Conclusion

Rajasthan's 2025 Wildlife Census shows a significant ecological shift: wildlife outside of sanctuaries and parks is much greater than within sanctuaries. The increase from 21,759 in 2014 to 2,71,813 in 2025 reflects a sharp rise in recorded wildlife numbers. To protect Rajasthan's wildlife, we must conserve forests outside sanctuaries, manage the water sources and engage the public.

MCQs

MCQ 1: What was the Rajasthan's wildlife count in 2025?

- A. 58,885
- B. 2,12,928
- C. 2,71,813
- D. 21,759

Answer: C

Explanation : In 2025, Rajasthan had a total wildlife count of 2,71,813. Of this, 58,885 animals were found in sanctuaries and parks and 2,12,928 animals were found in non-protected areas.

MCQ 2: Which technique is used by the Forest Department for wildlife census in Rajasthan on Buddha Purnima?

- A. Camera trap method
- B. Waterhole method
- C. Satellite mapping method
- D. Drone survey method

Answer: B

Explanation : The wildlife census in Rajasthan is done by waterhole method. This involves counting wildlife by keeping watch over water holes as during a period of drought, wildlife approach water holes within 24 hours.

MCQ 3: Why aren't Ranthambore, Sariska and Mukundra Hills Tiger Reserves included in the above wildlife census?

- A. They do not have wildlife populations
- B. They have a different counting method
- C. They are outside Rajasthan
- D. They were closed during the census

Answer: B

Explanation: Ranthambore, Sariska and Mukundra Hills Tiger Reserves were excluded from the data provided above because their counting methodology was different. So, their data were not merged with this tiger census data.

राजस्थान वन्यजीव गणना 2025 और अभयारण्यों व उद्यानों के बाहर वन्यजीव

राजस्थान में की गई **वन्यजीव गणना 2025** राज्य के वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाती है। वन विभाग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शाम 5 बजे से **जलस्रोत पद्धति** के माध्यम से वन्यजीवों की गणना करता है। इस पद्धति में जलस्रोतों के आसपास आने वाले वन्यजीवों की गिनती की जाती है। 2014 से 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुमानित वन्यजीव संख्या **2014 में 21,759** से बढ़कर **2025 में 2,71,813** हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभयारण्यों और उद्यानों के बाहर वन्यजीवों की संख्या इनके भीतर दर्ज संख्या से काफी अधिक है। 2025 में **58,885 वन्यजीव** अभयारण्यों और उद्यानों में पाए गए, जबकि **2,12,928 वन्यजीव** इनके बाहर दर्ज किए गए।

वन्यजीव गणना 2025 के प्रमुख बिंदु

- राजस्थान में 2025 में कुल **2,71,813 वन्यजीव** दर्ज किए गए।
- **58,885 वन्यजीव** अभयारण्यों और उद्यानों के अंदर पाए गए।
- **2,12,928 वन्यजीव** अभयारण्यों और उद्यानों के बाहर पाए गए।
- संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की संख्या अभयारण्यों और उद्यानों के अंदर दर्ज संख्या से **तीन गुना से अधिक** है।
- बुद्ध पूर्णिमा पर वन्यजीव गणना के लिए **जलस्रोत पद्धति** अपनाई जाती है।
- रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्यों को इस आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां गणना की पद्धति अलग है।

2014 से 2025 तक वन्यजीवों की वृद्धि

राजस्थान में पिछले 11 वर्षों में वन्यजीवों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2014 में अनुमानित संख्या 21,759 थी, जो 2025 में बढ़कर 2,71,813 हो गई। यह राज्य में वन्यजीवों की दर्ज संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

| वर्ष | कुल वन्यजीव | उद्यानों/अभयारण्यों के अंदर | संरक्षित क्षेत्रों के बाहर |
|------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2014 | 21,759 | आंकड़ा उपलब्ध नहीं | आंकड़ा उपलब्ध नहीं |
| 2017 | 2,23,933 | आंकड़ा उपलब्ध नहीं | आंकड़ा उपलब्ध नहीं |
| 2018 | 2,55,304 | 50,545 | 2,04,759 |
| 2019 | 2,52,342 | 66,837 | 1,85,505 |
| 2020 | 2,32,468 | 41,805 | 1,90,663 |
| 2022 | 2,43,284 | 56,378 | 1,86,906 |
| 2024 | 2,53,713 | 57,316 | 1,96,397 |
| 2025 | 2,71,813 | 58,885 | 2,12,928 |

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाए गए प्रमुख वन्यजीव

कई वन्यजीव प्रजातियां अभयारण्यों और उद्यानों के बाहर अधिक संख्या में दर्ज की गईं। यह संकेत देता है कि राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण को केवल संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

| प्रजाति | अभयारण्यों/उद्यानों के बाहर | अभयारण्यों/उद्यानों के अंदर | कुल |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| नीलगाय/रोजड़ा | 74,549 | 80 | 74,629 |
| चिंकारा | 12,385 | 15 | 12,400 |
| चीतल | 279 | 36 | 315 |

आंकड़ों का महत्व

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर संरक्षण

- आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के वन्यजीवों का बड़ा हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाया जाता है।
- इससे ग्राम आधारित संरक्षण और अभयारण्यों के बाहर संरक्षण में समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता बढ़ जाती है।
- संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की आवाजाही बेहतर जलस्रोत, चरागाह और वन प्रबंधन की आवश्यकता को भी दर्शाती है।

जलस्रोत पद्धति का महत्व

- जलस्रोत पद्धति में जल निकायों के आसपास आने वाले वन्यजीवों की गणना की जाती है।
- शुष्क राजस्थान में पशु सामान्यतः दिन में कम से कम एक बार जलस्रोतों पर आते हैं।
- इस कारण बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वन्यजीव गणना के लिए यह पद्धति उपयोगी मानी जाती है।

आंकड़ा संग्रह और गणना में सुधार

पहले वन्यजीव गणना के आंकड़े सीमित थे। 2001 से 2004 के बीच केवल पशुओं के नाम और सीमित संख्याएं दर्ज की जाती थीं। 2013 तक पूरे राज्य का पूर्ण आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं था। 2014 के बाद कुल संख्याएं व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाने लगीं। इसलिए 2014 के बाद का आंकड़ा राजस्थान में वन्यजीव प्रवृत्तियों को समझने के लिए अधिक उपयोगी है।

निष्कर्ष

राजस्थान की वन्यजीव गणना 2025 एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक बदलाव को दर्शाती है। अभयारण्यों और उद्यानों के बाहर वन्यजीवों की संख्या इनके भीतर दर्ज संख्या से काफी अधिक है। 2014 में 21,759 से बढ़कर 2025 में 2,71,813 तक पहुंची संख्या वन्यजीवों की दर्ज संख्या में तेज वृद्धि को दिखाती है। राजस्थान के वन्यजीवों की रक्षा के लिए अभयारण्यों के बाहर वनों का संरक्षण, जलस्रोतों का बेहतर प्रबंधन और जनभागीदारी आवश्यक है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1 : 2025 में राजस्थान में कुल कितने वन्यजीव दर्ज किए गए?

- A. 58,885
- B. 2,12,928
- C. 2,71,813
- D. 21,759

उत्तर: C

व्याख्या: 2025 में राजस्थान में कुल 2,71,813 वन्यजीव दर्ज किए गए। इनमें से 58,885 वन्यजीव अभयारण्यों और उद्यानों के अंदर पाए गए, जबकि 2,12,928 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर दर्ज किए गए।

प्रश्न 2 : बुद्ध पूर्णिमा पर राजस्थान में वन विभाग वन्यजीव गणना के लिए कौनसी पद्धति अपनाता है?

- A. कैमरा जाल पद्धति
- B. जलस्रोत पद्धति
- C. उपग्रह मानचित्रण पद्धति
- D. ड्रोन सर्वेक्षण पद्धति

उत्तर: B

व्याख्या: राजस्थान में वन्यजीव गणना जलस्रोत पद्धति से की जाती है। इसमें जलस्रोतों के आसपास निगरानी रखकर वन्यजीवों की गिनती की जाती है, क्योंकि शुष्क परिस्थितियों में वन्यजीव सामान्यतः 24 घंटे की अवधि में जलस्रोतों पर पानी पीने आते हैं।

प्रश्न 3 : रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्यों को दिए गए वन्यजीव गणना आंकड़ों में क्यों शामिल नहीं किया गया?

- A. वहां वन्यजीव नहीं हैं
- B. वहां गणना की पद्धति अलग है
- C. वे राजस्थान के बाहर हैं
- D. गणना के समय वे बंद थे

उत्तर: B

व्याख्या: रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्यों को दिए गए आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वहां वन्यजीव गणना की पद्धति अलग है। इसलिए उनके आंकड़ों को इस वन्यजीव गणना के आंकड़ों में नहीं मिलाया गया।